E Learning Study Material

By Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VKS UNIVERSITY ARA BIHAR

BA PART THIRD ECONOMICS HONS
PAPER SIX

TARIFF COMMISSION 1882 of USA

प्रशुल्क आयोग

President Chester A Arthur appointed a commission in May 1882 to recommend how much tariff rates should be reduced .. Support or opposition to tariffs often broke down along regional lines. In December 1882 the commission argued for substantial reductions.

इस प्रशुल्क आयोग ने प्रशुल्क दरों में 25 प्रतिशत कमी करने की सिफारिश की। किन्तु इस सिफारिश के बावजूद 1883 ई० के अधिनियम के अनुसार प्रशुल्क दर में केवल 5 प्रतिशत की कमी की गयी। इससे प्रशुल्क नीति काफी अधिक बदनाम हो गयी और हैरिसन राष्ट्रपति बना जिसके फलस्वरूप 1890 के मैक किनले टैरिफ ~~अधिनियम~~ अधिनियम के अनुसार सभी आयात वस्तुओं पर प्रशुल्क की दर में अत्यधिक वृद्धि की गयी। इसके अनुसार कृषि वस्तुओं को भी संरक्षण दिया गया। प्रशुल्क की दर औसतन 48.4 प्रतिशत हो गयी।

किन्तु प्रशुल्क की ऊँची दरों से जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो गयी। 1894 के विल्सन गोरमैन अधिनियम के अनुसार प्रशुल्क दरों में पर्याप्त कटौती की गयी। प्रशुल्क की दर अब औसतन 41.3 प्रतिशत हो गयी। 1893 ई॰ के बाद आर्थिक संकट आया। फिर 1896 ई॰ में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आयी। इसने 1894 ई॰ के अधिनियम को समाप्त कर दिया। एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार प्रशुल्क दरों में वृद्धि की गयी। 1897 का डिंगले टेरिफ अधिनियम 1864 के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशुल्क अधिनियम था जो लगभग 12 वर्षों तक चला। यद्यपि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति था तथापि इसके द्वारा उन सभी वस्तुओं को संरक्षण दिया गया जिनके लिए संरक्षण आवश्यक समझा गया। प्रशुल्क की औसत दर को बढ़ा कर 57 प्रतिशत किया गया। इसके अन्तर्गत बहुत सारी वस्तुओं पर कर लगाया गया। इस अधिनियम ने राष्ट्रपति को द्विपक्षीय समझौता का अधिकार दिया। फ्रान्स, इटली तथा पुर्तगाल के साथ इस प्रकार के समझौते किये गये। इस अधिनियम पर आधारित प्रशुल्क नीति लगभग 12 वर्षों तक चली इस काल में अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से प्रगति हुई। अतः इस समय प्रशुल्क में संशोधन की आवश्यकता नहीं हुई।